दैनिक जागरण
प्रेरणा की शक्ति से असंभव संभव होता है

गृह मंत्रालय की सख्ती

पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और साथ ही डॉक्टरों की हड़ताल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगकर अपने सख्त रवैये का ही परिचय दिया है। इसके पहले भी गृह मंत्रालय ने राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता सरकार को एडवाइजरी जारी कर कहा था कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया जाए और साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बार उसने एक ओर जहां डॉक्टरों की हड़ताल पर यह पूछा कि इस हड़ताल को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए वहीं दूसरी ओर यह विवरण भी मांग लिया कि बीते तीन सालों से जारी राजनीतिक हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या किया गया? ऐसे सवाल इसके बावजूद पूछे जाने चाहिए कि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है। यदि किसी राज्य में हालात एक सीमा से अधिक बिगड़ते हैं तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उन पर न केवल ध्यान दे, बल्कि ऐसे उपाय भी करे जिससे हालात संभलें। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जब देश के किसी हिस्से में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं तो उससे देश की छवि और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। हालांकि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर ममता सरकार का यही कहना था कि मोदी सरकार उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए उनकी पहल कहीं न कहीं यह संकेत दे रही है कि गृह मंत्रालय का दबाव रंग ला रहा है। यह रंग लाना भी चाहिए, क्योंकि एक तो मोदी सरकार कहीं अधिक राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता में लौटी है और दूसरे गृह मंत्रालय की कमान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के हाथ में आने के बाद यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि अब चीजें अलग ढंग से काम करेंगी। इसका एक बड़ा कारण अमित शाह की सख्त प्रशासक की छवि है।

अमित शाह वांछित नतीजों पर केंद्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। गृह मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि वह उन गतिविधियों को सहन करने वाले नहीं जो मोदी सरकार अथवा देश की छवि पर असर डालने वाली हों। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्होंने न केवल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक अनावश्यक ट्वीट पर उन्हें झिड़का, बल्कि गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को भी उनके एक बेजा बयान के लिए फटकारा। उनके ऐसे तेवरों को देखते हुए इस पर आश्चर्य नहीं कि गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर सख्ती दिखा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें यह समझें तो बेहतर कि अब गृह मंत्रालय राज्यों के हालात पर कहीं अधिक गहन निगाह रखेगा। यह समय की मांग भी है, क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं कि सैकड़ों लोगों की भीड़ किसी अस्पताल में धावा बोलकर डॉक्टरों को पीट-पीट कर अधमरा करा दे और फिर भी राज्य सरकार हिंसक तत्वों के खिलाफ कुछ न करे। ममता सरकार ने यही किया। राजनीतिक हिंसा पर भी उसका रवैया मनमानी वाला है। ऐसे हालात में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि गृह मंत्रालय सचेत और सक्रिय दिखे।

भाषा थोपने का प्रयास

केंद्र सरकार ने जब त्रिभाषी फॉर्मूला की बात कही थी, तब तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक के प्रमुख स्टालिन के सुर में बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी सुर मिलाया था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी पर कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही सियासत की अंधी दौड़ में वही ममता भूल गईं कि किसी पर कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती है। ममता ने कहा कि अगर आप बंगाल में हैं तो आपको बांग्ला भाषा बोलनी ही होगी। मैं ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करूंगी, जो बंगाल में रहते हैं और बाइक पर घूमते हैं। उनका यह इशारा कहीं और नहीं, भाजपा समर्थक हिंदीभाषियों पर था। उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता ने एक बार फिर बंगाल और बांग्ला की बात कर दी। यहां बताना आवश्यक है कि कांचरापाड़ा इलाका बैरकपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हिंदीभाषी अर्जुन सिंह को जीत मिली है। इस इलाके में हिंदीभाषियों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में क्या एक मुख्यमंत्री का उसी इलाके में जाकर यह कहना कि अमुक भाषा बोलनी होगी, क्या उचित है? क्या इससे भाषाई विभेद पैदा नहीं होगा? ममता का कहना है कि हमें बांग्ला को आगे लाना होगा। यह करने से उन्हें कौन रोक रहा है? हमारे देश के संविधान ने हरेक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह कहीं भी जा सकता है और कोई भी भाषा बोल सकता है। ऐसे में यह कहना कि बंगाल में रहते हैं तो बांग्ला भाषा बोलनी होगी, क्या सही है? ममता का कहना है कि जब मैं बिहार, यूपी, पंजाब जाती हूं तो वहां की भाषा बोलती हूं। क्या वह केरल, कर्नाटक जाएंगी तो कन्नड़, मलयालम बोल पाएंगी? इसपर विचार करने की जरूरत है। हर चीज में सियासत नहीं लानी चाहिए। जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो उसमें भी उन्हें साजिश दिख रही है। यही नहीं, दो वर्ष पहले सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने को लेकर कई माह तक दार्जिलिंग जला था। बावजूद इसके, उस घटना से सीख न लेकर भाषा पर विवाद पैदा करना सही नहीं है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए।

कठिन लक्ष्य है हर घर को नल से जल

संजय गुप्त

भारत में पेयजल की किल्लत का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि तमाम ऐसे इलाकों मे भी ट्यूबवेल से भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है जहां नल से जल भेजने की सुविधा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की दूसरी पारी में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है। इस मंत्रालय की कमान गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। शेखावत ने इस मंत्रालय की कमान संभालते ही यह घोषणा की कि अभी देश के 18 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही नल से जल की आपूर्ति होती है, लेकिन अगले पांच साल में शेष सभी 82 प्रतिशत घरों में भी नल से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस आशय का वादा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। इस वादे के अनुसार जल के लिए नया मंत्रालय बनाकर देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी नदियों को जोड़ने के अटल बिहारी वाजपेयी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण इलाकों में हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना चुनौती भरी है। यह चुनौती गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और शौचालयों का निर्माण कराने से अधिक कठिन है, लेकिन इसे पूरा करना भी आवश्यक है। यह योजना यह बताती है कि आजादी के 72 वर्षों बाद भी हम सभी को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत से पिछड़े कई देश अपने लोगों को बिजली, पानी एवं अन्य नागरिक सुविधाएं देने में समर्थ रहे हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो सभी को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखने में सक्षम हैं। यूरोपीय समुदाय में शामिल होने वाले देशों के सामने तो एक शर्त यह थी कि वे पेयजल संबंधी मानकों को पूरा करें। अपने देश में पेयजल के मामले में मानक तो बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से ही होता है। यही कारण है कि कई बड़े शहरों में भी गंदे जल की आपूर्ति की शिकायतें सामने आती रहती हैं। स्थानीय निकाय समुचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करने में अक्षम हैं।

एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर थी जो 2011 में 1544 क्यूबिक मीटर हो गई, लेकिन केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में पूरे देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1140 क्यूबिक मीटर रह जाने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे आती है तो उसे जल संकट माना जाता है। समस्या यह है कि देश के कई नदी बेसिन में जल उपलब्धता का पैमाना नीचे जा रहा है। इनमें कृष्णा, कावेरी, साबरमती भी हैं। इसे देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि देश का एक भाग रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। आज देश के कितने ही गांवों में महिलाओं को सिर पर पानी ढोकर मीलों चलना पड़ता है। कई जगह यह पानी शुद्ध भी नहीं होता। अनेक शहरों का भी बुरा हाल है। अनियोजित विकास ने हर घर को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को और मुश्किल बना दिया है। ध्यान रहे कि देश की राजधानी दिल्ली तक में ऐसे इलाके हैं जहां के लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। भारत में पेयजल की किल्लत का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि तमाम ऐसे इलाकों मे भी ट्यूबवेल से भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है जहां नल से जल भेजने की सुविधा है। इसके चलते भूजल स्तर गिरता जा रहा है। एक बड़ी समस्या यह है कि यह भूमिगत जल दूषित हो रहा है। कहीं-कहीं तो इतना दूषित हो गया है कि वह न तो पीने के लायक है और न ही सिंचाई के लायक। वह बीमारियां फैलाने का काम कर रहा है।

अवधेश राजपूत

अपने देश में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या आज से नहीं, आजादी के पहले से हैं। इसी तरह नदी जल के बंटवारे की समस्या भी बहुत पुरानी है। आज भी नदी जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों के बीच तनातनी है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी जल को लेकर विवाद है तो पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज नदी के जल को लेकर। देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो दूसरे देश से आने वाली नदियों के पानी से परेशान होते रहते हैं। पानी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सामाजिक-आर्थिक कारणों से भारत ढंग की कोई जल नीति नहीं बना पाया है। अब जब मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना आगे बढ़ा रही है तब फिर उसे इस पर ध्यान देना होगा कि नदियों के जल का ठीक से बंटवारा हो, भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन न हो, उसे प्रदूषित होने से रोका जाए और बारिश के जल का संरक्षण और संचयन हो। यदि बारिश के जल के एक चौथाई हिस्से को भी ढंग से संरक्षित और संचित किया जा सके तो पेयजल और सिंचाई के पानी की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा सके हैं। जो कदम उठाए भी गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। जल संरक्षण की योजनाएं सतत निगरानी और बेहतर रख-रखाव की मांग करती हैं। इसके अभाव में ये योजनाएं वैसे ही नाकाम हो सकती हैं जैसे सीवेज शोधन संयंत्र हो रहे हैं। जल संरक्षण की योजनाओं का नियमन और उनका रख-रखाव बेहतर ढंग से किया जाना इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जल संकट बढ़ता जा रहा है। जल संकट से बचने के लिए इस सवाल को भी सुलझाना होगा कि जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाए या नहीं?

आज देश के तमाम हिस्सों में छोटी-छोटी नदियां नालों में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ तो नष्ट होने की कगार पर हैं। नदियों के अलावा अन्य परंपरागत जलस्रोत भी अनदेखी का शिकार हैं। स्पष्ट है कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय को इन समस्याओं पर गंभीरता से गौर करना होगा। चूंकि केंद्र सरकार का काम नीतियां बनाना और उन पर अमल करना राज्यों का काम है इसलिए राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यह देखना होगा कि स्थानीय निकाय अपना काम सही ढंग से करें, क्योंकि पानी के प्रबंधन का काम उनके ही जिम्मे आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मोदी सरकार की हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यह तय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अच्छा-खासा धन चाहिए होगा। राज्यों ने इस योजना पर अमल के लिए जितने धन की जरूरत जताई है उससे यह स्पष्ट है कि अगले पांच सालों में केंद्र को इस योजना के मद में बड़ी धनराशि का प्रबंध करना होगा। अगर अगले पांच साल में इस योजना पर सही ढंग से अमल हुआ तो देश के लोगों को एक बड़ी राहत तो मिलेगी ही, मोदी सरकार को 2024 में वैसी ही राजनीतिक सफलता मिल सकती है जैसी हाल के आम चुनावों में गरीबों को रसोई गैस उपलब्ध कराने और उनके घरों में शौचालय निर्माण संबंधी योजनाओं से मिली।

response@jagran.com

कवि क्या कहना चाहता है

हास्य-व्यंग्य

साकेत सूर्येश

गालिब सपने में आए और एक तमाचा देकर कहने लगे, 'भाई, कवि कभी-कभी वही कहता है जो वह कहना चाहता है'

आत्मा-परमात्मा के रहस्यों, राजनीतिक सूक्ष्मताओं, ब्रह्माण्ड के रहस्य से भी अधिक गूढ़ और अधिक आनंददायक प्रश्न हिंदी साहित्य ने दिया है कि कवि क्या कहना चाहता है? यह एक प्रश्न है जिसे पहचानने की कला ने कई कवियों और समीक्षकों के जीवन की सार्थकता और करियर की सफलता निर्धारित की है। बड़े-बड़े अधिवेशनों में बड़े-बड़े बुद्धिजीवी इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में समय बिताते रहे हैं। गालिब ने एक शेर कहा था 'घर की दीवार पे खिला है सब्जा, हम हैं वीराने में आंगन में बहार आई है।' दो शताब्दी पहले और आज भी कई शोधकर्ता यह ढूंढने में अपनी साहित्यिक ऊर्जा का सदुपयोग करके संस्कृति मंत्रालयों से पारितोषिक और अकादमियों से नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं कि मिर्जा साहब यहां कहना क्या चाहते हैं?

एक कहता है कि शायद गदर के माहौल में गालिब के भीतर एक असहिष्णु राष्ट्रवादी आत्मा घुस गई और घर में छुपे गालिब साहब ने यह शेर फरमाया। एक दार्शनिक किस्म के बुद्धिजीवी के अनुसार गालिब साहब कबीर के विचारों में डूबे हैं और कहना चाहते हैं कि मैं दूसरों की बहार देख रहा हूं और मेरी आत्मा पर एक पतझड़ छाया हुआ है तथा मेरे सूखे हुए विचारों के पत्ते आत्मा के आंगन में गिर रहे हैं। एक गुलजारी प्रवृत्ति के लेखक लिखते हैं कि गालिब साहब कहना चाहते हैं कि 'सूखी हुई रूह पर धूप की पीली नमकीन रोशनी गिरती है और तुम, खूबसूरत सी, शाम के धुंधलके में आंगन में खिल रही हो।' उनकी समीक्षा की पृष्ठभूमि में वायलिन की ध्वनि डालकर ऑडियो बनाए गए जो युवा वर्ग द्वारा हाथों-हाथ लिए गए।

वामपंथी लेखक का कहना है कि गालिब साहब का तात्पर्य है कि सर्वहारा यहां वीराने में पड़ा है और बुर्जुआ वर्ग बहार का आनंद ले रहा है। वीराने में पड़े सर्वहारा का कर्तव्य है कि इस अत्याचार के विरोध में आवाज उठाए और 'होबे न, चोलबे न' के अमर नारे के साथ कमरे की दीवार गिराकर आंगन और सामने के फुटपाथ को घर के अंदर खींच ले। वामपंथी लेखक के वचनों को बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। पांच सितारा होटलों में पांच सितारा साहित्यकारों द्वारा उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ। उनकी गालिब की समीक्षा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हुई। गालिब के दीवान से अधिक उनकी समीक्षाएं बिकीं। वे एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए, अखबारों में लिखने लगे। तत्कालीन सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया, उस सरकार के गिरने के बाद उन्होंने नई सरकार के विरुद्ध पुरस्कार लौटाया और प्रबुद्ध चिंतक के रूप में उन्होंने देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की।

हमारे मित्र छगनलाल इन सब प्रेरणादायक प्रसंगों से बहुत उत्साहित हुए और एक दिन आकर बोले कि हम व्यंग्य का क्षेत्र छोड़कर समीक्षक बनेंगे और नामवर होंगे। छगनलाल के इस निर्णय के पीछे दो कारण थे। एक यह कि 'कवि क्या कहना चाहता है' में स्कोप अधिक है और दूसरा मुझे उलाहना देते हुए उन्होंने कहा कि व्यंग्यकार बनने में आगे कोई विकास नहीं है और बुढ़ापे में किचन गार्डन में टमाटर ही उगाने पड़ते हैं। वहीं एक कुशल समीक्षक आगे राजनीतिक प्रवक्ता बन कर भिन्न-भिन्न दलों के भिन्न-भिन्न सुप्रीम नेताओं की भावनाओं का अनुवाद राजनीतिक उपयोगिता के अनुसार कर सकता है-मसलन महान नेता ने सिर को चीन के विदेश मंत्री से मिलते हुए दाईं ओर झुकाया, सो इसका तात्पर्य यह है कि वह दक्षिणपंथ के साथ रहेंगे और वामपंथी शक्तियों का विरोध करेंगे। अतः उन्होंने समीक्षक बनने का निर्णय लिया और सफल समीक्षक के नाते सफल होने के बाद वे तय करेंगे कि किस नेता को अपना मुक्तिबोध मानकर वे उनकी तमाम वक्तव्यों का गूढ़ मंतव्य जनता तक ले जाएंगे।

हमने उनकी ओर भी गालिब का परिचित शेर फेंक कर पूछा कि कवि क्या कहना चाहता है? उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज का प्रदर्शन करते हुए कहा कि संभव है कि गालिब की सुंदर-सी पड़ोसन शक्कर लेने उनके घर पहुंची हो और गालिब साहब के मुंह से यह बात निकल गई हो कि आंगन में बहार आई है और एक निरीह पति की भांति हम यहां भीतर वीराने में बैठे हैं।

दूसरे दिन छगनलाल वापस आए और उनकी कांख में परसाई जी और शरद जी की पुस्तकें थीं। हमने पूछा कि वापस व्यंग्य की दुनिया की ओर लौट पड़ने का क्या तात्पर्य है? कहने लगे रात में गालिब उनके सपने में आए। एक तमाचा देकर कहने लगे, 'भाई, कवि कभी-कभी वही कहता है जो वह कहना चाहता है।' इसके बाद हमने वापस व्यंग्य की ओर लौटने का निर्णय लिया।

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता

कामयाबी के शिखर पर कुशलता के सोपानों से चढ़ा जाता है। सफलता बौद्धिक प्रतिभा का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता के समुचित सुनियोजन की कुशलता का नाम है। सफलता एक ऐसी तकनीक का नाम है, जो जाने हुए अर्जित ज्ञान को समय की मांग के अनुरूप क्रियाशील एवं क्रियान्वित कर सके। नई सोच, नए विचार और नित नई कुशलता सफलता के सूत्र हैं। ये सूत्र भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन में भी प्रयुक्त होते हैं। भौतिक जीवन के नूतन आविष्कार और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता इसी का परिणाम है। सफल होने के लिए समय एवं परिस्थिति के अनुरूप स्थिति को ढालने की आवश्यकता होती है।

पूर्वाग्रही, दुराग्रही और हठाग्रही व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों, मान्यताओं, आग्रहों और दुराग्रहों की सीमा में इस कदर कैद होते हैं कि वे इससे परे कुछ सोच ही नहीं सकते। ऐसी मानसिकता बदली हुई परिस्थितियों की आहट को सुनने-समझने में पूर्णतः असमर्थ होती है। किसी क्षेत्र में सफलता के लिए उस क्षेत्र के सारे आयामों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी वांछित विषय के स्वरूप को मनोयोगपूर्वक सही ढंग से समझना और उसे क्रियान्वित करने की तकनीक खोजना महत्वपूर्ण है।

कुशल कलाकार अपने कलात्मक कौशल से अपनी कला को सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। हमारे पास जो है या हम जिसे प्राप्त करने जा रहे हैं, उसे वर्तमान में कैसे उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाया जा सकता है? इस बात की खोज ही सफलता का आधार है। इसलिए सफल होने के लिए ज्ञानार्जन के अलावा इस बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हुए इस ज्ञान के प्रयोग की कुशलता का अभ्यास परम आवश्यक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता के लिए धैर्य की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार सफलता का भी कोई 'शॉर्टकट' नहीं होता। जब हम एक नियत समय तक प्रयास करेंगे तो कालांतर में उसका परिणाम मिलेगा। जितनी गलतियां कर सकें कर लें, लेकिन याद रखें इससे सीखने से ही आपको सफलता मिलेगी।

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

तथ्य-कथ्य

मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटों में वृद्धि

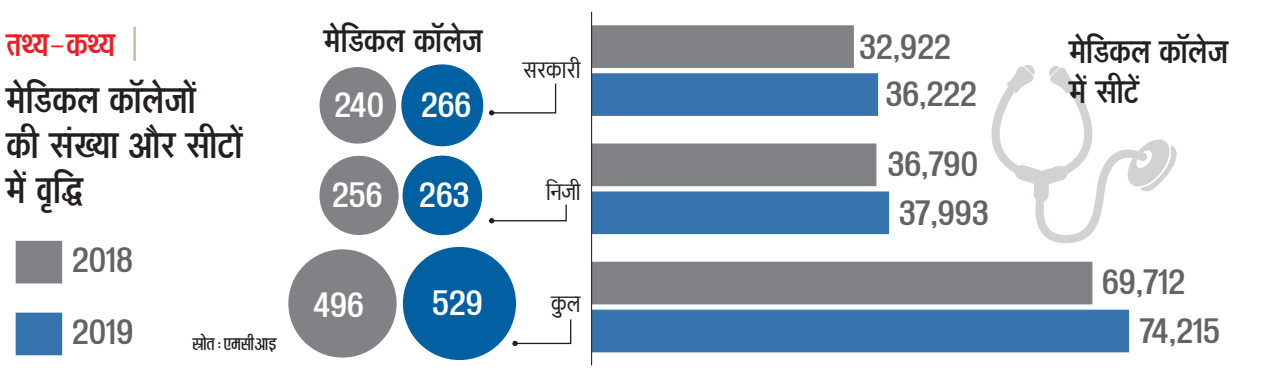

स्रोत : एमसीआइ

ट्रेन सफर पर लू का कहर

मुकुल व्यास

रेलवे को कुछ राहत वाले उपाय अवश्य करने चाहिए जिनमें दिन के वक्त ट्रेनों का नया समय निर्धारण शामिल है

उत्तर और मध्य भारत में गर्मी भीषण प्रकोप जारी है। मई के महीने में शुरू हुई गर्म हवाओं ने कम से कम 36 लोगों की जान ले ली है। कई शहरों में तापमान 50 और 46 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंच चुका है। भारत में इस साल गर्मी से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली मौतें रेल यात्रियों की थीं। झांसी से गुजर रही केरल एक्सप्रेस के गैर-एसी कोच में सवार चार सीनियर सिटीजन गर्मी नहीं झेल पाए। इस घटना ने रेल अधिकारियों को यह सोचने के लिए अवश्य मजबूर किया होगा कि गर्म प्रदेशों से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। भारत की पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनों के अधिकांश डिब्बों में एसी नहीं है और संसाधनों की कमी का तर्क देकर पूरी ट्रेन में एसी लगाने की बात तत्काल खारिज कर दी जाएगी, लेकिन रेलवे को इस दिशा में अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में गर्मी और ज्यादा विकट रूप धारण करेगी। ट्रेनों में गैर-एसी स्लीपर कोच की जगह एसी चेयर कार लगाई जा सकती हैं। रेलवे को कोच निर्माण के लिए गर्मी को परावर्तित करने वाले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। डिब्बों की छतों, बाहरी हिस्सों और शीशों में हीट-रिफ्लेक्टिव चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। साधारण डिब्बों में भीड़ न बढ़ने देने और उनमें वेंटिलेशन में सुधार की भी आवश्यकता है। डिब्बों पर थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद पानी का झिड़काव भी एक सुझाव हो सकता है, लेकिन पानी के लिए हाहाकार कर रहे देश में इसे लागू करना मुश्किल है। एसी के बगैर ट्रेनों में तापमान कम करना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। इसके लिए रेलवे आइआइटी जैसे संस्थानों की मदद ले सकता है। फिलहाल रेलवे को अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ राहत वाले उपाय अवश्य करने चाहिए जिनमें दिन के समय ट्रेनों का नया समय निर्धारण शामिल है।

दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तनों के बाद भारत में गर्मी तीव्र हुई है। पिछले दशक में गर्म हवाओं और लू का सिलसिला तेज हुआ है। 2015 में नौ राज्य लू से प्रभावित हुए थे, जबकि 2018 में 19 राज्यों को लू का प्रकोप झेलना पड़ा। इस साल यह संख्या 23 तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि इस साल लू वाले दिनों की संख्या भी बढ़ गई है। न सिर्फ दिन का तापमान अधिक रहता है, रात में भी तापमान ऊंचे स्तर पर बना रहता है।

दुनिया में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे, क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के बाद औसत तापमान ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि हर साल मौसम में कुछ भिन्नताएं होती हैं, लेकिन दुनिया का रुझान एकदम स्पष्ट है। इतिहास में दर्ज किए गए सबसे गर्म पांच वर्ष पिछले पांच वर्ष थे और सबसे ज्यादा गर्म 19 वर्षों में से 18 2001 से रिकॉर्ड किए गए हैं। दक्षिण एशिया के बड़े शहरों में जलवायु के रुझान के बारे में हाल में किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि यदि गर्मी का यह सिलसिला बना रहा तो इस सदी के अंत तक गर्मी और नमी का स्तर इतना ऊपर पहुंच जाएगा कि जो लोग छह घंटे या उससे अधिक समय तक प्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में आएंगे उनका जीवित रहना बड़ा मुश्किल होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

चर्चा में जदयू

ममता बनर्जी सरकार पर टिप्पणी करने के कारण जदयू से प्रवक्ता पद गंवा चुके अजय आलोक के प्रकरण ने राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा को गरम कर दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो ममता के चुनावी सलाहकार बनने गए थे। दूसरी तरफ अजय आलोक जिसने कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय पर टिप्पणी की थी, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। फंसे तब जब ममता पर बरसे। चर्चा के कारण प्रशांत किशोर और आलोक भले ही बने हों, केंद्रबिंदु में जदयू है। हालांकि जदयू नेतृत्व की ओर से बार-बार बोला जा रहा है कि भाजपा के साथ रिश्ते में सबकुछ सामान्य है, विधानसभा चुनाव भी दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जदयू के रुख की मीमांसा हर दल कर रहा है। भाजपा से ज्यादा विपक्षी दलों की नजरें बनी हुई हैं। संसद सत्र के दौरान इसकी परीक्षा होगी।

बेबस मन

नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के निजी सचिव को लेकर आए निर्देश ने नौकरशाहों के एक वर्ग पर मानो गाज गिरा दी है। सरकार ने तय कर दिया है कि पिछली सरकार में मंत्रियों के निजी सचिव रहे नौकरशाह इस बार बने नहीं रहेंगे। कुछ मंत्रियों के नए निजी सचिवों की तो नियुक्ति भी हो गई है। सरकार के इस कदम से नौकरशाही में हलचल सी मच गई है। कुछ निजी सचिव तो सलाहकार जैसे पदों में संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं तो बाकी मंत्रियों के साथ अपनी नियुक्ति की जुगत तलाश रहे हैं।

आजकल खामोश हैं

चुनाव के दौरान राजनीतिक बयान देकर सुर्खियों में छाए रहने वाले नीति आयोग के एक बड़े पदाधिकारी आजकल खामोश नजर आ रहे हैं। पहले जरा जरा-सी बात पर बयान देते थे, लेकिन अब बड़ी घटनाएं होने पर भी उन्होंने मौन साध लिया है। मसलन पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमणियन ने हाल ही में जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के बारे में बयान दिया तो उस पर न तो उन्होंने कोई ट्वीट किया और न ही कोई वक्तव्य जारी किया। उनकी यह खामोशी नीति आयोग के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर जब वह विदेश से पढ़े हुए अर्थशास्त्रियों को लेकर पहले ही कटाक्ष भरे बयान दे चुके हैं। ऐसे में इस बार जब अरविंद सुब्रमणियन ने यह बयान दिया तो उनसे उम्मीद थी कि सरकार पर हमले का वह जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जीडीपी को लेकर भी वह गाहे-बगाहे ज्ञान देते रहे हैं। बहरहाल जो भी हो उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों का फल तो मिल ही चुका है।

ट्वीट की नजाकत

ट्वीट आजकल विचारों के आदान-प्रदान का सबसे प्रचलित माध्यम तो बन गया है, लेकिन इस ट्वीट प्रेम के चक्कर में कुछ विचित्र वाकये भी हो जा रहे हैं। पिछले दिनों एक यूनियन के महामंत्री के कई परिजनों की कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस पर संबंधित मंत्रालय के दोनों मंत्रियों की ओर से ट्वीट कर संवेदना प्रकट की गई, लेकिन जिस हैंडल से ये ट्वीट किया गया उसमें दोनों मंत्रियों की फोटो अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में लगी हुई है। संवेदना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भाव-भंगिमा से भी जताई जाती है। मंत्री जी के ट्वीट में यह बिल्कुल उल्टा था। जाहिर है कि मंत्री के स्टाफ के संज्ञान में भी यह बात लाई गई और सलाह दी गई कि कम से कम ऐसे मौकों पर तो फोटो भी बदल दिए जाएं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।